



2026:AHC:66852

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 9502 वर्ष 2026

अनुराग कुमार @ अनुराग दुबे @ दबंग आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 65 (क्रम संख्या-296 वर्ष 296)

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दायर जवाबी हलफनामा और लिखित सबमिशन को अभिलेखों पर लिया जाता है।
3. आवेदक के अधिवक्ता श्री शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी और श्री अनूप त्रिवेदी, अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संजय सिंह और श्री सैनिक शंकर, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता-1 द्वारा सहायता प्राप्त की गई और अभिलेखों का अवलोकन किया।
4. आवेदक केस अपराध संख्या-63 वर्ष 2026 में धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एंटी सोशल एक्टिविटीज (रोकथाम) अधिनियम, 1986, थाना-मौदरवाजा, जिला फर्रुखाबाद, विचारण के लंबित रहने के दौरान ज़मानत मांगता है।

अभियोजन की कहानी:

5. सूचनाकर्ता द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें कहा गया था कि आवेदक अपने भाई अनुपम दुबे, विनीत इयूबी @ बीनू, विजय विक्रम, आशुतोष द्विवेदी @ बाँबी, आदेश सिंह, आशीष पांडे, धर्मेन्द्र चतुर्वेदी @ पप्पू चौबे, अमित कुमार @ अमित दुबे @ बब्बन, प्रवीण कटियार और महेन्द्र कटियार के साथ अवैध गतिविधियों में शामिल थे और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यूपी गैंगस्टर अधिनियम के तहत परिभाषित एक गिरोह के सदस्य हैं और उन पर यूपी गैंगस्टर एंटी सोशल एक्टिविटीज (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

आवेदक की ओर से तर्क:

6. आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है।

7. आवेदक को स्थानीय पुलिस द्वारा आवेदक के भाई के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के साथ मिलीभगत करके आरोपी बनाया गया है, जो प्रतिशोध के लिए एक राजनीतिक व्यक्ति है।

8. तैयार किए गए गैंग-चार्ट के अनुसार, आवेदक के खिलाफ दो मामले दिखाए गए अर्थात (i) केस अपराध संख्या-357 वर्ष 2023, धारा 147, 323, 506, 364-ए, 386, 341, 120-बी भ०द०वि० और आर्म्स एक्ट की 3/25, थाना-मौदरवाजा, जिला फर्रुखाबाद और (ii) केस अपराध संख्या-137 वर्ष 2024, धारा 323, 386, 447, 420, 467, 468, 471, 504, 506, 120-बी भ०द०वि०, थाना-मौदरवाजा, जिला फर्रुखाबाद हैं।

9. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कमरा संख्या-3/विशेष न्यायाधीश (डी.ए.ए.), फर्रुखाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.2.2025 के तहत अपराध संख्या-357 वर्ष 2023 में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उक्त आदेश को जमानत आवेदन के साथ दायर हलफनामे के अनुलग्नक-3 के रूप में संलग्न किया गया है।

10. गैंग-चार्ट में दिखाए गए एक अन्य मामले में, यानी केस अपराध संख्या-137 वर्ष 2024, आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष अपराध विविध रिट याचिका संख्या-13935 वर्ष 2024 दायर की, जिसे दिनांक 13.8.2024 के आदेश द्वारा निपटाया गया और आवेदक को अग्रिम जमानत या नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया।

11. इस न्यायालय के दिनांक 13.8.2024 के उक्त आक्षेपित आदेश के खिलाफ, आवेदक ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की विशेष अनुमति (क्रि.) संख्या-14624 वर्ष



2024 को दायर की, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 28.11.2024 के अपने आदेश के माध्यम से निम्नलिखित आदेश पारित किया: -

4. हालांकि, किसी भी परिस्थिति में, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना या तो उसके खिलाफ पहले से दर्ज मामलों में या उसके खिलाफ दर्ज किए जा सकने वाले नए मामले में पुलिस हिरासत में नहीं लिया जाएगा।

12. उपरोक्त आदेश को संशोधित किया गया था और इस न्यायालय के 13.8.2024 के आक्षेपित आदेश को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.1.2025 के अपने अंतिम आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था और निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था: -

"13. जहां तक दिनांक 28.11.2024 के आदेश का संबंध है, इसे इस हद तक संशोधित/स्पष्ट किया जाता है कि यदि अपीलकर्ता के खिलाफ कोई नई शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का खुलासा किया गया है, तो प्राथमिकी केवल क्षेत्राधिकार सत्र न्यायाधीश की पूर्व अनुमति से ही दर्ज की जाएगी।

13. सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 20.1.2025 के पूर्वोक्त आदेश के अनुसार, आवेदक सभी मामलों में विचारण न्यायालय के समक्ष पेश हुआ और जमानत के लिए आवेदन किया और उसे उन सभी मामलों में जमानत दे दी गई है।

14. उक्त मामलों के अलावा, आवेदक 26 और मामलों में वांछित है। उक्त मामलों का विवरण इस प्रकार है: -

क्रम संख्या।	प्राथमिकी/अपराध नंबर	स्थिति
1	केस अपराध संख्या-05 वर्ष 2004, धारा 447, 323, 452 भ०द०वि०, थाना-कोतवाली, जिला फर्रुखाबाद।	क्लोजर रिपोर्ट दिनांक 25.05.2025 के आदेश द्वारा स्वीकार कर ली गई।
2	केस अपराध संख्या-504 वर्ष 2005, धारा 147, 148, 149, 302 भ०द०वि०, थाना-बेवर, जिला मैनपुरी।	क्लोजर रिपोर्ट दिनांक 04-04-2006 के आदेश द्वारा स्वीकार कर ली गई थी।
3	केस अपराध संख्या-611 वर्ष 2000, धारा 147, 148, 149, 307 भ०द०वि०, थाना-कोतवाली फर्रुखाबाद, जिला फर्रुखाबाद।	दिनांक 25-05-2007 के आदेश के तहत विचारण न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया।
4	केस अपराध संख्या-838 वर्ष 2010, गुंडा एक्ट की	कार्यवाही 29.05.2015 को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



क्रम संख्या।	प्राथमिकी/अपराध नंबर	स्थिति
	धारा 3/4 के तहत, थाना-कोतवाली फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद।	समाप्त कर दी गई थी।
5	केस अपराध संख्या-742 वर्ष 2010, धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 404/149 भ०द०वि० और 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, थाना-कोतवाली फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद।	दिनांक 18.01.2012 के आदेश के तहत विचारण न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया।
6	केस अपराध संख्या-939 वर्ष 2020, धारा 147, 148, 149, 307, 386, 452, 504, 506, 427, 286, 323, 336, 120-बी भ०द०वि० और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, थाना-कोतवाली फर्रुखाबाद, जिला फर्रुखाबाद।	आवेदक को अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 13.10.2021 के आदेश के तहत जमानत दे दी गई है।
7	केस अपराध संख्या-357 वर्ष 2021, धारा 384, 504, 506 भ०द०वि०, थाना-कोतवाली फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद।	आवेदक को 20.10.2021 को जमानत दी जाती है।
8	केस अपराध संख्या-382 वर्ष 2021, धारा 419, 420, 467, 468, 471 भ०द०वि०, थाना-कोतवाली मोहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद।	आवेदक को 10.02.2022 को जमानत दी जाती है।
क्रम संख्या	प्राथमिकी/अपराध नंबर	स्थिति
9	केस अपराध संख्या-899 वर्ष 2021, यूपी गैंगस्टर एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट की धारा 3(1) के तहत, थाना-कोतवाली फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद।	आवेदक को दिनांक 09.02.2022 के आदेश के तहत जमानत दी जाती है।
10	केस अपराध संख्या-525 वर्ष 2021, धारा 395, 341, 504, 506, 323, 427, 354-केएच भ०द०वि०, थाना-कोतवाली छिबरामऊ, जिला कन्नौज।	आवेदक को दिनांक 16.02.2022 के आदेश के तहत जमानत दी जाती है।
11	केस अपराध संख्या-661 वर्ष 2021, यूपी गैंगस्टर एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज (रोकथाम) अधिनियम की धारा 3(1) के तहत, पी.एस.	आवेदक को 05.04.2025 को बरी कर दिया गया।
12	केस अपराध संख्या-465 वर्ष 2022, धारा 147, 386, 447, 420, 467, 471, 506 भ०द०वि०, थाना-कोतवाली, जिला फर्रुखाबाद।	आवेदक की गिरफ्तारी पर दिनांक 26.05.2023 के आदेश के तहत रोक लगाई जाती है।
13	केस अपराध संख्या-466 वर्ष 2022, धारा 147, 386, 447, 420, 467, 471, 506 भ०द०वि०, थाना-कोतवाली फर्रुखाबाद, जिला फर्रुखाबाद।	दिनांक 07.04.2023 के आदेश के तहत आवेदक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है।
14	केस अपराध संख्या-467 वर्ष 2022, धारा 147,	दिनांक 07.04.2023 के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



क्रम संख्या।	प्राथमिकी/अपराध नंबर	स्थिति
	386, 447, 420, 467, 471, 506 भ०द०वि०, थाना-कोतवाली फर्रुखाबाद, जिला फर्रुखाबाद।	आदेश के तहत आवेदक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है।
15	केस अपराध संख्या-09 वर्ष 2023, धारा 147, 148, 149, 342, 386, 447, 427, 506, 420, 467, 468, 471 भ०द०वि०, थाना-कोतवाली फर्रुखाबाद, जिला फर्रुखाबाद।	आवेदक को दिनांक 01.02.2025 के आदेश के तहत जमानत दी जाती है।
16	केस अपराध संख्या-111 वर्ष 2023, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भ०द०वि० और एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस), थाना-मौदरवाजा, जिला फर्रुखाबाद।	आवेदक को दिनांक 30.05.2025 के आदेश के तहत जमानत दी जाती है।
17	केस अपराध संख्या-557 वर्ष 2022, धारा 386, 342, 420, 467, 468, 471, 506, 120-बी भ०द०वि०, थाना-कोतवाली, जिला फर्रुखाबाद।	आवेदक को दिनांक 01.02.2025 के आदेश के तहत जमानत दी जाती है।
18	केस अपराध संख्या-69 वर्ष 2022 (केस संख्या-1617/2022), गुंडा एक्ट की धारा 2/3 के तहत, थाना-मोहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद।	दिनांक 28.08.2023 के आदेश के तहत कार्यवाही समाप्त कर दी गई है।
19	केस अपराध संख्या-69 वर्ष 2023, धारा 363, 342, 386, 504, 506, 34 भ०द०वि०, थाना-कोतवाली मोहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद।	आवेदक को दिनांक 07.02.2025 के आदेश के तहत जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
20	केस अपराध संख्या-736 वर्ष 2022, धारा 147, 420, 406, 120बी, 506, 342, 384, 389 भ०द०वि०, थाना-कोतवाली छिबरामऊ, जिला कन्नौज।	आवेदक को दिनांक 07.04.2025 के आदेश के तहत छुट्टी दे दी गई है।
21	केस अपराध संख्या-258 वर्ष 2023, यूपी गैंगस्टर एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट की धारा 3(1) के तहत, पी.एस.	आवेदक की गिरफ्तारी पर दिनांक 30.04.2024 के आदेश द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत करने तक रोक लगा दी गई है।
22	केस अपराध संख्या-219 वर्ष 2023, धारा 420, 386, 506, 120बी भ०द०वि०, थाना-मोहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद।	आवेदक को दिनांक 03.02.2025 के आदेश के तहत जमानत दी जाती है।
23	केस अपराध संख्या-443 वर्ष 2023, धारा 174ए भ०द०वि०, थाना-मौदरवाजा, जिला फर्रुखाबाद।	आवेदक को दिनांक 01.02.2025 के आदेश के तहत जमानत दी जाती है।
24	केस अपराध संख्या-487 वर्ष 2023, धारा 409, 174ए भ०द०वि०, थाना-मौदरवाजा, जिला फर्रुखाबाद।	आवेदक को जमानत दे दी जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



क्रम संख्या।	प्राथमिकी/अपराध नंबर	स्थिति
25	केस अपराध संख्या-216 वर्ष 2024 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भ०द०वि०, थाना- मौदरवाजा, जिला फर्रुखाबाद।	आवेदक को दिनांक 01.02.2025 के आदेश के तहत जमानत दी जाती है।
26	केस अपराध संख्या-179 वर्ष 2024 धारा 147, 148, 149, 386, 364, 365, 367, 323, 504, 506, भ०द०वि०, थाना-मौदरवाजा, जिला फर्रुखाबाद।	आवेदक को दिनांक 01.02.2025 के आदेश के तहत जमानत दी जाती है।

15. उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद, पुलिस ने उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए आवेदक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और उसे जेल भेज दिया। यह सच है कि प्राथमिकी के अनुसार, क्षेत्राधिकार सत्र न्यायाधीश द्वारा 11.2.2026 को अनुमति दी गई थी, जबकि गैंग-चार्ट 5.2.2026 को ही तैयार किया गया है, जो क्षेत्राधिकार सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद से ली गई अनुमति से पहले है। पुलिस ने यूपी गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों के तहत चार प्राथमिकी दर्ज की थीं, जिसमें आवेदक के खिलाफ वर्तमान प्राथमिकी भी शामिल थी।

16. वर्तमान प्राथमिकी सिर्फ उसे और अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों को परेशान करने के लिए स्थापित की गई है। आवेदक न तो गिरोह का नेता है और न ही किसी गिरोह का सक्रिय सदस्य है। उसे उसके बड़े भाई अनुपम दुबे की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण झूठा फंसाया गया है, जो एक वयस्क है।

17. राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण पुलिस द्वारा और उनके कहने पर अन्य व्यक्तियों द्वारा कई प्राथमिकी दर्ज की गईं और उच्चतम न्यायालय ने 20.1.2025 के अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि आवेदक के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी, जो स्थानीय पुलिस के हाथों गड़बड़ी का संकेत देती हो।

18. आवेदक इलाके का एक प्रामाणिक और कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है क्योंकि वह श्याम जनता विद्यालय फर्रुखाबाद का प्रधानाध्यापक था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आवेदक ने उस गिरोह के सदस्य के रूप में कोई पैसा कमाया जिसके लिए उसे स्थानीय पुलिस द्वारा बुक किया गया है।



19. आवेदक अनुपम दुबे के भाई ने 14.07.2021 को आत्मसमर्पण कर दिया था और उसके बाद उनके और आवेदक के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।

20. आवेदक ने स्वयं वर्ष 2010 में नगर पंचायत के सभापति का चुनाव लड़ा था और फिर से बसपा के टिकट पर विधान सभा सदस्य का चुनाव लड़ा था और सत्तारूढ़ दल से संबंधित स्थानीय विधायक आगामी विधान सभा चुनाव के आलोक में आवेदक को किसी न किसी बहाने सलाखों के पीछे रखने पर आमदा है।

21. आवेदक प्रस्तुत मामले के अपराध में 12.02.2026 से केवल उसकी कोई गलती नहीं होने के कारण जेल में है। आवेदक के फरार होने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि प्रस्तुत मामले में, सभी गवाह पुलिस के गवाह हैं।

22. आवेदक को साजिश की भूमिका सौंपी गई है, लेकिन आवेदक और सह-आरोपी व्यक्ति के दिमाग में मिलने का कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा, आवेदक का भाई 14.7.2021 से जेल में है, इस तरह, उसके लिए उसके साथ साजिश रचने और गिरोह बनाने का कोई अवसर नहीं था।

23. ऊपर उल्लिखित अपराध के मामले में, यानी प्राथमिकी संख्या-939 वर्ष 2020, आवेदक का नाम जांच के दौरान 20 महीने बाद सामने आया है और आवेदक को गिरफ्तार कर लिया गया था और उस पर एक साथ आठ मामले थोप दिए गए थे। ऊपर उल्लिखित कुल मामलों में से पुलिस द्वारा आवेदक के खिलाफ नौ प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

24. प्राथमिकी संख्या-465 वर्ष 2022, 466 वर्ष 2022 और 467 वर्ष 2022 को एक के बाद एक स्थापित किया गया था ताकि आवेदक को वर्ष 1999 में एक भूमि के अवैध कब्जे के संबंध में सलाखों के पीछे रखा जा सके। उक्त भूमि राज्य की भूमि पाई गई और उस पर सूचनाकर्ता की इमारतें खड़ी की गईं, न कि आवेदक और उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। उक्त तथ्य बेईमानी का संकेत देता है।

25. स्थानीय पुलिस की दुर्भावना इस तथ्य से स्थापित होती है कि केस अपराध संख्या-504 वर्ष 2005 में, पुलिस ने पहले ही जांच की थी और क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी, जिसे सक्षम अदालत ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन लगभग 20 वर्षों की अवधि



के बाद, पुलिस अधिकारियों ने इस तथ्य को जानने के बावजूद उक्त मामले में आगे की जांच करने का प्रयास किया कि मामले को वर्ष 2006 में बहुत पहले ही अंतिम रूप दिया गया था।

26. प्रस्तुत मामला अलग है क्योंकि यूपी गैंगस्टर अधिनियम की धारा 19(4) में उल्लिखित शर्तें पूरी नहीं होती हैं क्योंकि यह पुलिस के साथ मिलीभगत में स्थानीय राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के सत्ता के दुरुपयोग और प्रभाव का एक स्पष्ट मामला है और उनका दुर्भावनापूर्ण इरादा उन परिस्थितियों से स्पष्ट है जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले ही नोट किया गया था।

27. आवेदक के अधिवक्ता ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2020 (11) एस.सी.सी. 648** में पारित निर्णय पर बहुत भरोसा किया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का लंबित होना ज़मानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है, यदि अन्यथा ज़मानत के लिए उसका मामला बन जाता है।

28. इसी तरह, उच्चतम न्यायालय ने **मौलाना मो. अमीर रशादी बनाम यूपी राज्य और अन्य, 2012 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू 1048** में माना गया है कि आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि ज़मानत से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है और अदालत को आरोपी और अन्य उपस्थित परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार भूमिका पर विचार करने की आवश्यकता है।

29. गौरव @ गौरा बनाम यूपी राज्य (आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-13747 वर्ष 2021) में पारित इस न्यायालय के फैसले पर बहुत भरोसा किया गया है, जिसके तहत आरोपी को इस तथ्य के बावजूद ज़मानत दी गई थी कि उसका 48 मामलों का आपराधिक आपराधिक इतिहास है।

30. अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक के अधिवक्ता ने **[2007 (1) जेआईसी 680 (इलाहाबाद)] पवन कुमार पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले पर भी भरोसा किया, जहां आरोपी कथित तौर पर भ०द०वि० की धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के कमीशन में शामिल था, अदालत द्वारा यह माना गया है कि यदि आरोपी अन्यथा ज़मानत का



हकदार है, तो इसे केवल आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया है कि उक्त मामले में आरोपी 56 आपराधिक मामलों में वांछित था।

31. इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानूनों के अनुसार - "ज़मानत देने का प्रभाव प्रतिपक्षी (अभियुक्त) को मुक्त करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे कानून की हिरासत से रिहा करने और उसे अपने ज़मानतदारों की हिरासत में सौंपने के लिए है जो उसे एक निर्दिष्ट समय और स्थान पर अपने मुकदमे में उपस्थित होने के लिए पेश करने के लिए बाध्य हैं।

32. विधि आयोग की 268 वीं रिपोर्ट (2017) के अनुसार, 'ज़मानत' का अर्थ अनिवार्य रूप से हिरासत में रखे गए अपराध के संदेह वाले व्यक्ति की न्यायिक अंतरिम रिहाई है, एक मान्यता में प्रवेश करने पर, ज़मानत के साथ या बिना, कि संदिग्ध बाद की तारीख में आरोपों का जवाब देने के लिए प्रकट होगा; और कानून के तहत किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपराध के आरोपी व्यक्ति को ज़मानत देना शामिल है।

33. कमलापति त्रिवेदी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1979 ए.आई.आर. (एस.सी.) 777 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ज़मानत को मानवीय मूल्यों की दो बुनियादी अवधारणाओं के संश्लेषण को प्रभावित करने के लिए एक तकनीक के रूप में तैयार किया गया है, अर्थात् अभियुक्त को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक हित का आनंद लेने का अधिकार; जिसके अधीन, अभियुक्त व्यक्ति को मुकदमे में खड़े होने के लिए अदालत में पेश करने के लिए ज़मानत पर रिहाई की शर्त है।

34. इसी तरह के सह-आरोपी आदेश सिंह को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-9975 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 24.3.2026 के आदेश द्वारा ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है, इस प्रकार, आवेदक भी समानता के आधार पर ज़मानत का हकदार है।

35. सह-आरोपी व्यक्ति आशीष पांडे की कार्यवाही पर इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या-4952 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 17.3.2026 के आदेश के माध्यम से रोक लगा दी गई है। 36. इस प्रकार, इन परिस्थितियों और ऊपर उल्लिखित



कानून के तहत, आवेदक ज़मानत का हकदार है। वह मुकदमे में सहयोग करने और ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करने का वचन देता है।

राज्य/सूचनाकर्ता की ओर से तर्क:

37. ज़मानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया है कि आवेदक एक आपराधिक इतिहास वर्ष 29 मामलों वाला व्यक्ति है, जिसमें प्रस्तुत मामला और गिरोह चार्ट में उल्लिखित मामले शामिल हैं। उसके खिलाफ 17 जीवित मामले लंबित हैं, हालांकि यह स्वीकार किया जाता है कि 12 अन्य मामलों का निपटारा किया जाता है और आवेदक को उन मामलों में से किसी में भी दोषी नहीं ठहराया जाता है।

38. विधेय अपराध में केवल ज़मानत देना यूपी गैंगस्टर अधिनियम के तहत ज़मानत देने का आधार नहीं होगा, क्योंकि अधिनियम की धारा 19(4) के तहत प्रावधान प्रस्तुत मामले पर लागू होंगे। यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि आवेदक पहले किए गए अपराध को नहीं दोहराएगा। वह बार-बार अपराधी है।

39. यह आरोप कि प्राथमिकी उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी द्वारा स्थापित की गई है, झूठे हैं, क्योंकि सभी मामलों में सूचनाकर्ता पूरी तरह से अलग हैं।

40. किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में बहुत ही बुनियादी कानून को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि स्वतंत्रता पर विचार किया जाना है, तो एक ओर, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता निर्णय का प्रश्न हो सकती है, लेकिन सामाजिक आदेश आवेदक को ज़मानत से इनकार करने का एक निर्णायक कारक है।

41. आवेदक के पास अपने क्रेडिट के लिए लंबे समय से आपराधिक पृष्ठभूमि है, इस तरह, वह ज़मानत का हकदार नहीं है।

42. अनिल सिंह @ दाऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2008 एस.सी.सी. ऑनलाइन इला 1809 में इस न्यायालय के फैसले के निम्नलिखित प्रस्तर पर बहुत भरोसा किया गया है: -

"4. इसलिए, ज़मानत केवल तभी दी जानी चाहिए जहां यह मानने के लिए उचित आधार हों कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है।



5. अभियुक्त की ओर से दलीलें यह थीं कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने वाले अन्य मामलों में, उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है और वह पिछले छह महीनों से हिरासत में है, यह अकेले यह विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रदान नहीं करेगा कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है।

6. आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वह एक गिरोह का नेता है जो असामाजिक गतिविधियों में लिप्त है और उसने क्षेत्र में आतंक पैदा किया है और कोई भी उसके खिलाफ सबूत देने के लिए तैयार नहीं है, भय और प्रतिशोध का कारण बनता है।

43. साबिर खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, 2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन इला 411 में रिपोर्ट किया गया था, इस न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है:

"10. इस अधिनियम में ज़मानत आवेदन का निपटान करते समय न्यायालय द्वारा इन परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस प्रावधान का अनुपालन केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन न्यायालय गैंग बैंड अधिनियम के तहत ज़मानत याचिका पर विचार करते समय इस प्रावधान पर विचार करना चाहिए और आदेश में भी परिलक्षित होना चाहिए, भले ही वह संक्षिप्त हो। इस प्रावधान को किसी भी मामले में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

11. साथ ही, अदालत को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रतिशोध लेने के लिए एक हथियार के रूप में, या निर्दोष नागरिकों को परेशान करने या डराने या राजनीतिक प्रतिशोध या अन्य उत्पीड़न के लिए। इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है और यदि ऐसा है, तो इसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

विश्लेषण

12. आवेदक ने आवेदन के पृष्ठ 7 और 8 में अपने आपराधिक इतिहास का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है: -



- (1) धारा 411, 413, 414 एस.डी. अधिनियम के तहत;
- (2) एमयू संख्या-426/2019 धारा 413, 414 थाना-अचनरा, जिला आगरा के विवेचनाधिकारी के तहत;
- (3) एमओयू संख्या-428/2019 धारा 413, 414 विवेचनाधिकारी के तहत स्टेशन, अचनेर, जिला आगरा के तहत;
- (4) एमयू संख्या-429/2019 धारा 413, 414 थाना-अचनरा, जिला आगरा के विवेचनाधिकारी के तहत;
- (5) एमयू संख्या-08/2019 के तहत जगनेर, जिला आगरा की धारा संख्या-413, 414 विवेचनाधिकारी।
- (6) एमयू संख्या-308/2019 धारा 380, 457, 411 विवेचनाधिकारी फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा।
- (7) एमओयू संख्या-145/2019, धारा 413, 414 विवेचनाधिकारी, थाना-बसई अरेला, जिला आगरा के तहत;
- (8) एमयू संख्या-345/2019, पुलिस स्टेशन, जिला आगरा की धारा 411, 414 विवेचनाधिकारी के तहत;
- (9) एमओयू संख्या-419/2019, धारा 395, 412 विवेचनाधिकारी, खंडौली, जिला आगरा।

13. उपरोक्त से यह ज्ञात है कि आवेदक एक आदतन अपराधी है जिसका उपयोग उसी प्रकार का अपराध करने के लिए किया जाता है। जैसा कि "गिरोह अधिनियम" की धारा 2 (बी) और (सी) में परिभाषित किया गया है, जैसा कि क्रमशः "गिरोह" और "गिरोह" में परिभाषित किया गया है, आवेदक भी एक गिरोह का सदस्य है जो एकल या सामूहिक रूप से असामाजिक है। जो दंड संहिता, 1860 1860 (एसडी नं) के अध्याय 16 या अध्याय 17 या अध्याय 22 के तहत दंडनीय अपराध करता है। यहां यह बताना उचित होगा कि आवेदक द्वारा किया गया अपराध दंड संहिता, 1860 के अध्याय 17 के तहत



दंडनीय है। प्रथम दृष्टया, प्रस्तुत मामले में, इस अदालत को यह हल करना होगा कि यह मानने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है कि आवेदक इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है। तत्स्य विपरीत, वर्तमान परिस्थितियों में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह एक उचित आधार है कि यह अदालत यह समाधान ढूँढ सकती है।

14. इसके अलावा, आवेदक का एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है, इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई दुविधा नहीं है कि वह एक आदतन अपराधी है। इसलिए, इस अदालत के लिए यह हल करने का कोई उचित आधार नहीं है कि आवेदक को जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। बल्कि, यह अधिक संभावना है कि आवेदक जमानत पर रहते हुए एक समान या अन्य अपराध करेगा।

44. नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य [आपराधिक अपील संख्या-1272 वर्ष 2015 (@ एसएलपी (क्रिल०) संख्या-1596 वर्ष 2015)]

"15. यह कानून की स्थिति होने के कारण, यह बादल रहित आकाश की तरह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों के आपराधिक पूर्ववृत्त को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। उच्च न्यायालय के साथ जो बात प्रभावित हुई है वह समानता का सिद्धांत है। अपराधों की प्रकृति में शामिल एक हिस्ट्री-शीटर जिसे हमने यहां ऊपर पुनः प्रस्तुत किया है, मामूली अपराध नहीं हैं ताकि उसे हिरासत में न रखा जाए, लेकिन अपराध जघन्य प्रकृति के हैं और इस तरह के अपराध, किसी भी तरह की कल्पना से, जेजुन के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस तरह के मामले एक विश्लेषणात्मक दिमाग में मूसलाधार बारिश की संभावना के प्रभाव से गड़गड़ाहट और बिजली पैदा करते हैं। कानून न्यायपालिका से उम्मीद करता है कि इस तरह के अभियुक्त व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर स्वीकार करते समय सतर्क रहें और इसलिए, विवेकपूर्ण तरीके से विवेक का प्रयोग करने पर जोर दिया जाता है, न कि सनकी तरीके से।

45. कमलेश पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2023: एचसी:47620 में इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"22. लैटिन शब्द 'एक्टस रीस' का अर्थ है दोषी कार्य। इस प्रकार, यह अपराध का भौतिक घटक है। यह सच है कि आपराधिक कृत्य के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता है। हमें एक्टस रीस के साथ-साथ मेन्स रिया / आशय / इरादा पर भी विचार करना होगा। एक्टस रीस दोषी कार्य के लिए लैटिन है और मेन्स रीआ दोषी मन के लिए लैटिन है। आपराधिक कार्य को पूरा करने के लिए दोनों तत्वों की आवश्यकता होती है। अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की सामग्री से एक्टस रीस और मेन्स री का अनुमान लगाया जाना चाहिए, जिसमें आवेदक को आपराधिक पृष्ठभूमि बताई जाती है और उक्त विधेय अपराध में, आवेदक ने अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को मृतक और घायल व्यक्तियों पर गोली चलाने के लिए प्रोत्साहित किया था। इस प्रकार, एक्टस रीस और मेन्स रिया / आशय / इरादा का तत्व उक्त मामले में मौजूद है और गिरोह का नेता होने के नाते, प्रस्तुत मामले में भी उसी को स्थान मिलता है।

23. एक गैंगस्टर के संबंध में, परिस्थितियों से एक अनुमान निकाला जा सकता है। यहां अपराधी एक विधायिका उर्फ एक पूर्व मंत्री है, लेकिन वही उसे अवैयक्तिक गतिविधियों से मुक्त नहीं कर सकता है।

24. यह सच है कि सामान्य परिस्थितियों में, यदि अन्यथा ज़मानत के लिए अपराधी का मामला बनाया जाता है, तो आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यहां अपराध की गंभीरता और आपराधिक पृष्ठभूमि भी आवेदक के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती का प्रयास और जालसाजी आदि के मामले हैं।

25. यह सच है कि कानूनों के दुरुपयोग की संभावना है जो भी इसे निष्पादित करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। प्रस्तुत मामला अधिनियम का दुरुपयोग प्रतीत नहीं होता है और आवेदक का इतना बड़ा आपराधिक इतिहास है और गिरोह का वयस्क होने के नाते ज़मानत का हकदार नहीं है।

26. अभिलेखों के अवलोकन से, मुझे यह विश्वास करने के लिए उचित आधार नहीं मिलते हैं कि आवेदक इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और ज़मानत



पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है जैसा कि अधिनियम की धारा 19(4) की आवश्यकता है।

27. पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और मामले के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, न्यायालय की राय है कि यह ज़मानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। इसलिए, आवेदक की ज़मानत याचिका एतद्वारा खारिज कर दी जाती है।

46. यह न्यायालय ज़ेबा रिजवान बनाम यूपी राज्य द्वारा प्रधान सचिव गृह कार्यालय (आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-4691 वर्ष 2022) ने निम्नानुसार अवलोकन किया है:

"23. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और मामले की परिस्थितियों को देखने और इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि आवेदक के खिलाफ केवल एक मामला लंबित है और वह भी एक आपराधिक साजिश का, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) में निर्दिष्ट दोहरी शर्तें संतुष्ट हैं और यह ज़मानत के लिए एक उपयुक्त मामला है।

47. गोलू यादव उर्फ सुदीप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-1513 वर्ष 2025) में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:

"11. इस प्रकार, इस न्यायालय के लिए यह मानने का कोई उचित आधार नहीं है कि आवेदक ऐसे अपराधों का दोषी नहीं है और आवेदक को भविष्य में ज़मानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है, जैसा कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम की धारा 19(4) की आवश्यकता है।

48. इमरान मुल्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-17326 वर्ष 2025) में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:

"9. इस तथ्य को देखते हुए कि आवेदक का लंबा आपराधिक इतिहास है जो 2013 से 2023 तक है और आवेदक पर दो बार गैंगस्टर अधिनियम लगाया गया है, गैंगस्टर अधिनियम की धारा 19(4)(बी) के तहत कोई संतुष्टि दर्ज



नहीं की जा सकती है। आवेदक को जमानत पर रिहा करने का कोई मामला नहीं बनता है। यदि आवेदक को जमानत पर बढ़ाया जाता है, तो वह बड़े पैमाने पर समाज के लिए खतरा होगा। इसके अलावा, दूसरी जमानत याचिका में कोई नया आधार नहीं उठाया गया है और खंड पीठ ने सत्य पाल (उपरोक्त) के मामले में पहले ही यह विचार किया था कि जब तक नया आधार मौजूद नहीं है, तब तक दूसरी जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है।

49. धारा 19(4) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1986 में वह प्रावधान है जिसके तहत एक आरोपी जमानत का दावा कर सकता है। उप-धारा इस प्रकार है: -

धारा 19(4) :- संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय अपराध का अभियुक्त कोई भी व्यक्ति, यदि हिरासत में है, तो उसे जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक:

(क) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है, और

(बी) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, न्यायालय संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। उपखंड

(ख) यहां प्रासंगिक है। इस खंड में, यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी व्यक्ति को केवल तभी जमानत पर रिहा किया जा सकता है जब जमानत आवेदन की सुनवाई करने वाली अदालत संतुष्ट हो कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।



निष्कर्ष:

50. धारा 19(4)(बी) में निहित प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ज़मानत आवेदन की सुनवाई करने वाली अदालत के समक्ष यह विश्वास करने के लिए उचित आधार होना चाहिए कि आवेदक आरोपी उसके द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध का दोषी नहीं है और आगे यह कि ज़मानत पर रहने के दौरान उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

51. "जब तक दोषी साबित न हो जाए" का प्रसिद्ध सिद्धांत "जब तक दोषी साबित न हो, एक नियम के रूप में ज़मानत और अपवाद के रूप में कारावास की अवधारणा को जन्म देता है।

52. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता है क्योंकि उस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है जब तक कि अपराध उचित संदेह से परे स्थापित नहीं हो जाता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी का भी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, और प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, 2022 आई.एन.एस.सी. 690** में दोहराया गया है।

53. उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 आई.एन.एस.सी. 595** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से इस बात पर जोर दिया है कि कानून के बहुत अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत कि ज़मानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, को भुलाया नहीं जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि अदालतों को इस सिद्धांत को पहचानना चाहिए कि "ज़मानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है"।

54. अपर महाधिवक्ता किसी भी असाधारण परिस्थितियों को सामने नहीं ला सकता है जो आवेदक को ज़मानत से इनकार करने की गारंटी देगा।



55. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि ज़मानत का उद्देश्य मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति को सुरक्षित करना है। अपर महाधिवक्ता द्वारा आवेदक के न्याय से भागने या न्याय के प्रविधि को बाधित करने या अपराधों को दोहराने या गवाहों को डराने आदि के रूप में अन्य परेशानियों पैदा करने का कोई भौतिक विवरण या परिस्थितियां नहीं दर्शाई गई हैं।

56. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा दी गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गिरोह चार्ट में उल्लिखित दो मामले और आपराधिक इतिहास वर्ष 26 अतिरिक्त मामले, आवेदक द्वारा ठीक से समझाए गए हैं और 28.11.2024 और 20.1.2025 को पारित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि गिरोह का नेता, आवेदक का भाई, 14.07.2021 से जेल में है; आरोपी व्यक्तियों में से एक को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है और कार्यवाही को एक अन्य सह-आरोपी व्यक्ति के रूप में रोक लगा दी गई है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने ज़मानत के लिए मामला बनाया है। ज़मानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

57. आवेदक- अनुराग कुमार @ अनुराग दुबे @ डब्लन को संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, ज़मानतदारों के सत्यापन के अधीन, इस शर्त के साथ कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या गवाहों को डराएगा और आवश्यकतानुसार विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा।

58. किसी भी शर्त का उल्लंघन ज़मानत को रद्द करना होगा। यहां टिप्पणियां योग्यता के आधार पर मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगी।

(कृष्ण पहल)

मार्च 30, 2026

विकास वर्मा